

प्रेस रिलीज / 25 अप्रैल 2021

तेलंगाना में 16 संगठनों पर प्रतिबंध एक दमनकारी फैसला: पॉपुलर फ्रंट

नई दिल्ली: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव अनीस अहमद ने अपने एक बयान में तेलंगाना में 16 संगठनों को प्रतिबंधित करने के राज्य सरकार के फैसले पर कड़ा विरोध जताया है।

यह बड़ी गंभीर बात है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनो गई एक राज्य सरकार इस बड़ी कार्यवाही के द्वारा संगठनों पर प्रतिबंध लगा रही है। इस विवादास्पद फैसले के पीछे बताए गए कारण अस्पष्ट हैं और इससे यह शक मजबूत होता है कि यह केवल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ राज्य सरकार की इत्तेकामी कार्यवाही है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में राज्य या केंद्र सरकार की नीतियों के लोकतांत्रिक विरोध के प्रति सहिष्णुता का रवैया होना चाहिए।

पॉपुलर फ्रंट का मानना है कि विचारों के खिलाफ ताकत से नहीं लड़ा जा सकता। समाज में लोकतांत्रिक तरीके से काम करने की गुंजाइश न देना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर से लोगों का भरोसा खो देगा। अगर सरकार के पास किसी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि का सबूत है, तो उसे उसके खिलाफ मुकदमा दायर करके अदालत में हाजिर करना चाहिए और अपने दावे को साबित करना चाहिए। लेकिन ऐसा न करके इस तरह की दमनकारी कार्यवाही करना एक चिंताजनक बात है और यह एक लोकतांत्रिक समाज के लिए हानिकारक है। दुर्भाग्य की बात है कि भले ही तेलंगाना की जनता ने बीजेपी को सिर्फ एक सीट देकर पूरी तरह से नकार दिया है, लेकिन टीआरएस सरकार सामाजिक संगठनों और नागरिक अधिकार समूहों के साथ मामला करने में बीजेपी की केंद्र सरकार की तरह ही दमनकारी नीतियों पर अमल कर रही है। पॉपुलर फ्रंट तेलंगाना सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करता है।

डायरेक्टर, मीडिया एवं जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली